ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 31-33
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-8, No.-II, Issues-IX YEAR- Dec-2017

वैश्वीकरण ....विभिन्न परिदृश्य में

रामकृष्ण उपाध्याय

विभागाध्यक्ष– अर्थशास्त्र ,कुँवर सिंह पी0जी0 कालेज, बलिया (उ0प्र0) भारत

नई शिक्षा ,औद्योगिक आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (Liberalization, Privatization and Globalization) जिसे भारत ने 24 जुलाई, 1991 में लागू किया, उससे भारत की भौतिक समृद्धि निःसंदेह अपार बढ़ी है। भारत ने विश्व में विकसित एवं आत्मनिर्भरता की पहचान बनाई है, परन्तु दूसरी ओर सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्य की घोषणायें मात्र कल्पना बन कर रह गयी हैं। अमीरी–गरीबी की खाई अत्यधिक चौड़ी हुई है। ग्रामीण किसान, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, आदिवासी तथा विशेषज्ञतारहित युवा, L.P.G. के चकाचौंध तथा इस गला–काट प्रतिस्पर्धा में बहुत ही पीछे छूटते जा रहे है। वे भुखमरी के कगार पर हैं। उपभोक्ता संस्कृति एवं बाजारीकरण ने नारी तथा अन्य सामाजिक मूल्यों को बिकाऊ बना दिया है। अपराधिता एवं सम्पन्नता एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये है।/1

नई शिक्षा ,औद्योगिक आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (Liberalization, Privatization and Globalization) जिसे भारत ने 24 जुलाई, 1991 में लागू किया उससे भारत की भौतिक समृद्धि निःसंदेह अपार बढ़ी है। भारत ने विश्व में विकसित एवं आत्मनिर्भरता की पहचान बनाई है परन्तु दूसरी ओर सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्य की घोषणायें मात्र कल्पना बन कर रह गयी हैं। अमीरी–गरीबी की खाई अत्यधिक चौड़ी हुई है। ग्रामीण किसान, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, आदिवासी तथा विशेषज्ञतारहित युवा, L.P.G. के चकाचौंध तथा इस गला–काट प्रतिस्पर्धा में बहुत ही पीछे छूटते जा रहे है। वे भुखमरी के कगार पर हैं। उपभोक्ता संस्कृति एवं बाजारीकरण ने नारी तथा अन्य सामाजिक मूल्यों को बिकाऊ बना दिया है। अपराधिता एवं सम्पन्नता एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये है।

इन दिनों हम दो प्रकार के भारत के टकराव के बारे में काफी सुनते हैं। जैसे कहा जाता है कि गाँवों का भारत और शहरों का भारत, वंचितों का भारत और शाइनिंग इंडिया का भारत। इनके बीच की दूरियाँ एवं अन्तराल एवं खाई दिनोंदिन काफी लम्बी चौड़ी होती जा रही है। विकसित भारत, सर्वसम्पन्न भारत एवं वैश्विक स्तर पर नये समृद्ध भारत के निर्माण की दृढ़ संकल्पता, हमें क्या प्रदान कर रही है तथा हम निरन्तर क्या पा रहे हैं या क्या खोते जा रहे हैं, इसका मूल्यांकन समय रहते करना अपरिहार्य है। वर्तमान में हमारी समस्त विकासात्मक कल्पनायें साकार होने के लिये बेकरार हैं, जो इस और यह तीव्रतर गति से प्रवाहित वैश्वीकरण की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में ही गहन चिन्तन का प्लेटफार्म प्रदान कर रहीं है। वैश्वीकरण आखिर है क्या? क्या यह नये युग की देन है? क्या यह विकसित देशों की देन है? या सर्वमान्य आदर्श विकासमान एवं समष्टि के लिये सुखदायी कोई नया फार्मूला है? वास्तविकता यह है कि कोई नयी अवधारणा नहीं हैं। सदियों पहले भारत ने अपनी आध्यात्म आधारित संस्कृति का प्रचार–प्रसार किया था। गणित, ज्योतिष, चिकित्सीय ज्ञान, आणुविक तथा ज्ञान–विज्ञान का प्रचार–प्रसार तथा लघु एवं कुटीर औद्योगिक उत्पादित की उपलब्धता पूरे विश्व में मात्र भारत ने ही करायी थी। परन्तु उक्तकाल का उद्देश्य मात्र सर्वे भवन्तु सुखिनः का था। 'आनो भद्रा कृत्वो यन्तु विश्वतः' का सिद्धान्त था।3 दूसरा दौर, वैश्वीकरण का उस समय देखा गया जब विदेशी आक्रान्ता जैसे यूनानी योद्धा सिकन्दर, मंगोल, चंगेज खाँ, तातार खाँ, गजनी आदि क्रूर आततायियों ने दुनियाँ के दूरस्थ स्थानों पर बसे आबादियों पर आक्रमण करके, मारपीट हत्यायें करके अमिट छोड़ना चाहते थे। तीसरा दौर, योरोपीय देशों का जैसे अंग्रेजों का आया जिन्होंने पूरे विश्व में व्यापार के बहाने अपना राज्य कायम किया था। उनका एकमात्र यही उद्देश्य रहा कि अन्य देशों की शिक्षा, भौतिक सुविधाओं एवं धार्मिक, राजनैतिक वैचारिकी को अर्थात पूरे विश्व को अंग्रेजित में रूपान्तरित करके उन पर थोप दी जाय। इस दौरान भी उनका कोई मानव कल्याणकारी आदर्श नहीं छुपा था। बल्कि समस्त मानवता गुलामी की जंजीरों में जकड़ती चली गई। शताब्दियों तक अपने प्राणों की आहुति देकर शासित देश स्वतन्त्रता के लिये व्याकुल हो उठे थे।

15 अगस्त 1947 को भारत भी इस स्वतन्त्रता के क्रम में स्वतन्त्र हुआ। आर्थिक सामाजिक विकास माडल के लिये तत्कालीन राजनेताओं ने मिश्रित अर्थ व्यवस्था को सोवियत संघ पैटर्न पर स्वीकार किया। Philonthrophical आदर्शो से ओत–प्रोत भारत के तत्कालीन नेताओं ने सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक आर्थिक विकास को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से काफी दूर तक आगे ले जाने का व्रत लिया था। सोवियत संघ के विघटन,

अनुरूपी लेखक

खाड़ी देशों में शीत युद्ध, सत्ता की बढ़ती लोलुपता तथा सत्ता में अपराधिक तत्वों के निरन्तर आगमन ने 80 के दशक में भारतीय स्वदेशी आर्थिक स्थिति को अधिक जर्जर बना दिया। गर्भस्थ शिशु भी अन्तर्राष्ट्रीय कर्ज में डूब गया। ऐसी भयावह स्थिति से उबरने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव मंत्रिमण्डल के तत्कालीन वित्त मंत्री एवं वर्तमान में प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह द्वारा 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक आर्थिक नीति लागू करने के साथ ही आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया गया। तभी से नये सिद्धान्तों, वैचारिकी, प्रतिमानों, बहुयामी उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की कल्पनाओं से सुसज्जित वैश्वीकरण Globalization द्वारा भारत को भी अपने रंग में रंगने के लिये शामिल कर लिया गया। इस नई आर्थिक नीति के प्रमुख घटक ही उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण है जो सभी समस्याओं के लिए राम बाण माने गये। इसे L.P.G. के रूप में जाना जाता है। 1. Liberalization, 2. Privatization, 3. Globalization

1. उदारीकरण वह आर्थिक प्रक्रिया है, जिसमें कठोरतायें न हों एवं प्रक्रिया सम्बन्धी अनावश्यक विलम्ब न हो जिसके कारण भ्रष्टाचार को एवं अकुशलता को प्रोत्साहन मिलता है तथा उत्पादन हतोत्साहित होता है। इसमें शासन द्वारा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में लाइसेंस नियंत्रण, कोटा एवं शुल्क आदि प्रशासकीय अवराधों को कम करने तथा अथवा उदार बरतने का प्रयास किया जाता है। इसके अन्तर्गत सम्मिलित है 1. औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर देना। 2. आय पर लगाये गये बाह्य प्रतिबन्धों को समाप्त कर देना। 3. आयात ड्यूटी को कम कर देना, 4 वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाना, 5. विदेशी निवेश के प्रति उदारपूर्ण नीतिअपनाना, प्रतिबन्धों को कम कर देना, 6. सार्वजनिक क्षेत्र के रेखांकित क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिये खोल देना तथा 7. अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धी बनाना।

उदारीकरण व्यवस्था का मूलमंत्र है मुक्त बाजार। इस प्रकार उन्मुक्त बाजार व्यवस्था का परिणाम यह है कि पूरा विश्व एक बाजार हो गया (Global Market)। इससे प्रतिस्पर्धात्मक (Competitive), उत्पादकता (Producttivity), गुणवत्ता (Qualitative) एवं कार्य कुशलता (Effeciency) में वृद्धि होगी। इस समस्त प्रक्रिया के पीछे यही धारणा रही है कि इससे आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु राष्ट्रीय आय विकसित हो सकेगी एवं समृद्धि आ जायेगी।4

निजीकरण (Privatization): निजीकरण का अर्थ है स्वामित्व एवं नियंत्रण, सरकार के हाथों से निकलकर दूसरे गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं एवं कारपोरेट जगत में हस्तान्तरित हो जाना। यह उदारीकरण का अभिन्न अंग है। यह उद्योग व्यवसाय एवं सेवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्रों में हस्तान्तरण को प्रश्रय देता है, क्योंकि निजी क्षेत्र गुणवत्ता एवं दक्षता का प्रतीक माना जाता है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र को अकुशलता व भ्रष्टाचार का द्योतक माना जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों को पूर्ण या आंशिक रूप से निजी उद्योगपतियों को बेच दिया जाता है। इस नयी आर्थिक नीति में स्वयं सरकार अपनी अनेक जिम्मेदारियों को कम करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अनेक उत्पादक श्रेत्रों को निजी (Private) क्षेत्रों को बेच देती है।5

साम्राज्यवाद (Imperialism) से सम्बन्धित विश्वव्यापी संवृत्ति वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण एकरूपता एवं समरूपता की वह प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रों के बीच की भौगोलिक दूरियाँ कम हो जाती हैं। सम्पूर्ण विश्व सिमट कर एक भूमण्डलीय गाँव (Global Village) के रूप में विकसित हो जाती है। वैश्वीकरण क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रवाह से जोड़ना है, इसे जोड़ने का कार्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ (Multinational Companie) करती हैं तथा भूमण्डलीय जनमाध्यम संचार प्रणाली करती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आर्थिक लाभ है वह भी वैश्विक पैमाने पर। इसलिये इसकी बलवती इच्छा यही रहती है कि सभी राष्ट्रों को विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) के ढांचे के आधीन कर लिया जाय। इसीलिये वैश्वीकरण के प्रणेता विचारक आयात प्रतिस्थापन व्यापार की नीति की अपेक्षा निर्यात प्रेरित विकास नीति को अपनाने पर विशेष बल देते हैं।6

वैश्वीकरण की परिभाषा में तीन ही विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है। (1)निर्बाध व्यापार प्रवाह (2) निर्बाधा पूंजी प्रवाह, (3) निर्बाध तकनीकी प्रवाह। वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, जो प्रौद्योगिकी के उच्च प्रौद्योगिकी में रूपान्तरण के साथ आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में व्यापक एवं द्रुतगामी परिवर्तनों के रूप में परिलक्षित होती है। समाजशास्त्री इसे समाज की प्रकृति में खुलापन एवं क्रियात्मक परिक्षेत्र में विस्तार के रूप में देखते है। राजनीतिवेत्ता इसकी विवेचना में नागरिकता एवं राज्य की सीमाओं में शिथिलता को महत्व देते है। जबकि सांस्कृतिक मानवशास्त्री इसे सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वास प्रतिमानों तथा जीवनशैली में आयातित संस्कृतियों द्वारा परिवर्तन को महत्व देते है। दूसरी ओर अर्थशास्त्री इसे वित्त, व्यापार एवं आर्थिक कार्य व्यवहार में स्वतन्त्रता, खुलापन एवं स्वायतता निरूपित करते हैं। उदारवादी विचारकों का मानना है कि उत्तरोत्तर वैश्वीकरण की प्रक्रिया दृढ़ हुई है।7

मूल्यांकन–उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण– नई आर्थिक नीति को लागू हुए लगभग बीस वर्ष होने जा रहे हैं। मुद्रास्फीति की दर में कमी, औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि, बैंक ऋण दरों में कमी, एवं शेयर बाजार के

इंडेक्स में वृद्धि उदारीकरण की उपलब्धियां मानी जा रही है। वर्तमान में 5500 कम्पनियाँ शेयर बाजार में पंजीकृत हो चुकी है। उदारीकरण से बैंकिंग क्षेत्र को लाभ पहुंचा है। बैंकों के पास अत्यधिक ऋण देने के लिये धन उपलब्ध हो रहे हैं। इससे प्रत्येक भारतीय लाभ उठा सकता है। शिक्षा ऋण योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा आदि। व्यक्तिगत ऋण की सरल प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 11 अरब रूपये का निकास 2009–10 में की गई जिसमें से बड़ी राशि शेयर बाजार में लगाये गये। छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिये केन्द्र सरकार ने नये कम्पनी कानून में बड़े प्रावधान करने का भी फैसला किया है।

उदारीकरण का कृष्ण पक्ष उपलब्धियों की तुलना में अत्यधिक काला है। जहाँ एक एक ओर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रोत्साहन मिला वहीं दूसरी ओर इसने कृषकों की रीढ़ तोड़ दी। सभी उत्पाद आलू (चिप्स में), टमाटर (सॉस में), नमक (आयोडीन नमक में), तेल, घी, कपास अनेक कृषि उत्पादों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपने कब्जे में ले लिया। ब्रान्डेड उत्पाद के रूप में बेचकर लगातार अरबपति हो गये। दूसरी ओर कृषक इतने गरीब होते गये है कि वे आत्म हत्या तक करने के लिये विवश हो रहे है। छोटे काश्तकार जमीन बेचकर औद्योगिक नगरीय क्षेत्रों में जाकर नौकरी की तलाश कर रहे हैं।8 निराशा छोड़कर उन्हें वहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। बड़े बड़े उद्योग तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उच्च प्रौद्योगिकी के आइने में अति विशेषज्ञों को ही नौकरी देती है। सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार बहुत कम होते जा रहे हैं। यद्यपि निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत अधिक बढ़े है, परन्तु वर्तमान परिदृश्य में किसान, कमजोर वर्ग एवं सदियों से शोषित दलित वग अनेक कारणों से वंचित हो रहे है। जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक न्याय एवं समानता का सिद्धान्त कोरी कल्पना सिद्ध हो रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या 102 करोड़ में कुल श्रमिकों की संख्या 40.25 करोड़ है जिसमें 31.07 करोड श्रमिक गांवों में बसते है तथा 9.18 करोड नगरों में बसते है। सीमान्त श्रमिकों की संख्या 8.93 करोड है जबकि मुख्य मुख्य श्रमिकों की संख्या 31.23 करोड़ है। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या 10.74 करोड है जो कृषि मौसम में ही रोजगार पा सकते हैं। घरेलू औद्योगिक श्रमिकों की संख्या है जो 5 लाख लघु उद्योगों के बन्द होने के कारण बेकार हो चुके है तथा अन्य श्रमिकों की संख्या क्रमशः 1.64 करोड़, तथा 2.93 करोड़ है। दसवी योजना में लक्षित 8 प्रतिशत वार्षिक की विकास दर प्राप्त करने के उपरान्त मात्र 29.76 प्रतिशत व्यक्ति वर्ष रोजगार के अवसर ही सृजित हुए, जबकि श्रम बल की वृद्धि 1.8 प्रतिशत वार्षिक रही, जो पूर्ण रोजगार के वादे से काफी दूर है।9 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999), सम्पूर्ण ग्रामीण योजना (2001), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000) जय प्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना (2003), तथा मनरेगा योजना निसंदेह स्वागत योग्य है, परन्तु घोटाला तथा भ्रष्टाचार कारणों से कागजी कार्यवाही ही अधिक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बेनान जे एवं डंकली, डी 2000, Globalization : The Reader, London, The Ethlon Press.
2. नई आर्थिक नीति और सामाजिक न्याय – डॉ0 राम गोपाल सिंह
3. आर्थिक उदारीकरण के बीहड़ में सामाजिक न्याय का भटकाव – बी.के.कुमावत
4. Singh Yogendra, 2000, Cultural Change in India Rawat Publications, Jaipur.
5. Singh S. K. Economic Reforms In India, Employment News 22 (32) 1995
6. Misra Girishwar, 2006 Hkwe.Myhdj.k] ekDlZokn] fgUnqLrku 30 tqykbZ] 2006
7. डॉ0 श्रीवास्तव, राजीव कुमार, वैश्वीकरण एवं समाज, वैभवलक्ष्मी प्रकाशन ,वाराणसी ,पृ0 76.79,2013।
8. Times of India 30/09/1995
9. भारतीय अर्थव्यवस्था, रूद्रदत्त एवं के.पी. सुन्दरम।
10. अमर्त्य सेन, आर्थिक विकास एवं स्वातन्यत्र।
11. Text Economic Reforms : A Discussion Paper issued by Government of India
12. Narlikar 2005 बदलती दुनियाँ में हिन्दुस्तान' नवभारत जनवरी 8.
13. गौरीशंकर 'नई आर्थिक नीति : उपलब्धियों के विविध आयाम,' गाँधी विचार (291) 26-54.1993.

*****